अध्याय-I

विहगावलोकन*

वर्ष 2002-03 के दौरान गतिविधियाँ

1.1 वर्ष 2002-03 में ऊर्जस्वित सेवा क्षेत्र के साथ-साथ औद्योगिक वृद्धि में भी बहाली देखी गयी । तथापि, कृषि क्षेत्र में सूखे की स्थिति बनी रही और वर्ष 2002-03 के लिए समग्र सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर मंद रही। औद्योगिक वृद्धि में पुनः तेजी आने के अनुरूप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाद्येतर ऋण के उठाव में भी कुछ वृद्धि हुई, विशेषकर, 2002-03 के उत्तरार्ध में। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संविभाग में, आस्तियों की दृष्टि से अग्रिमों के पक्ष में कुछ झुकाव हुआ। अग्रिमों की तुलना में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता निर्धारित अपेक्षित स्तर से काफी अधिक होने तथा ब्याज दरों में गिरावट आने के कारण, उनकी प्रमुख आय में कोषागार से प्राप्त आय का हिस्सा मुख्य बना रहा। गैर-निष्पादक आस्तियों के अनुपात में गिरावट आयी। अनेक पहलें की गयीं, जैसे कि बेहतर जोखिम प्रबंध की परम्पराएं तथा बेहतर वसूली प्रयास जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफैसी) अधिनियम 2002 के हाल ही में पारित होने से प्रेरित रही।

1.2 सहकारी बैंकों ने मामूली-सी वृद्धि दर्शायी और उनकी लाभप्रदता कम संतोषजनक रही। विकास वित्त संस्थाओं की गतिविधियों में कुछ कमी आयी जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का कार्य-निष्पादन 2001-2002 में कम संतोषजनक रहा। वहीं अग्रणी आकंड़ों ने 2002-2003 के दौरान उस स्थिति में सुधार के कुछ संकेत दिये। रिज़र्व बैंक द्वारा अनेक विनियामक उपाय किये गये, जैसे - इस क्षेत्र की ब्याज दरों को अर्थव्यवस्था के शेष क्षेत्रों में विद्यमान ब्याज दरों के अनुरूप बनाना, विवेकसम्मत मानदण्डों को कठोर करना, परिचालन प्रक्रियाओं का मानकीकरण और पर्यवेक्षी दिशानिर्देशों का समन्वयीकरण ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को और आगे बढ़ाया।

व्यापक परिवेश

1.3 वर्ष 2002-03 के लिए 4.3 प्रतिशत समग्र सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर 2001-02 के 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर से निम्न थी, जिसका मुख्य कारण है - 14 वर्षों में पड़े सबसे भयंकर सूखे के कारण कृषि के सकल देशी उत्पाद में 3 प्रतिशत से अधिक की कमी का आना । दूसरी ओर, औद्योगिक उत्पादन ने व्यापक रूप से ऊर्ध्वमुखी वृद्धि दर्शायी। सेवा क्षेत्र में वृद्धि भी उच्चतर थी, जिसका मुख्य कारण था - निर्माण, देशी व्यापार, और परिवहन, 'वित्तपोषण', बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाओं के क्षेत्रों में उच्चतर वृद्धि दर कर होना। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर थोक मूल्य सूचकांक) मध्य-जनवरी 2003 तक निम्न बनी रही, परंतु, उसके बाद मार्च 2003 के अंत तक बढ़ गया जिसका कारण था - खाद्येतर वस्तुओं और खनिज तेल के मूल्यों में आयी तेज वृद्धि। 2002-03 के वर्ष के पूरे लिए मुद्रास्फीति कुल मिलाकर थोक मूल्य सूचकांक की दृष्टि से 2001-02 के 3.6 प्रतिशत की तुलना में 3.4 प्रतिशत पर कुछ निम्नतर रही।

1.4 विश्वव्यापी मंदी और अनिश्चय के परिवेश के होते हुए भी, वणिक निर्यातों में तेज वृद्धि, सॉफ्टवेयर जैसे उच्चतर सेवाएं, निर्यात तथा भारी आवक विप्रेषण से प्रेरित होकर भुगतान संतुलन के चालू खाते ने वर्ष 2002-03 के दौरान 4.1 बिलियन अमरीकी डालर (सकल देशी उत्पाद के 0.8 प्रतिशत) का अधिशेष दर्शाया । 2002-03 के दौरान निवल पूंजी आगम बढ़कर 12.1 बिलियन अमरीकी डालर का हो गया। पूंजी खाते में इस सुधार के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार मार्च 2002 के अंत के 54.1 बिलियन अमरीकी डालर से काफी बढ़कर मार्च 2003 के अंत में 75.4 बिलियन अमरीकी डालर का हो गया।

1.5 देशी अर्थव्यवस्था में, चलनिधि की स्थितियां वर्षभर सुविधाजनक बनी रहीं। व्यापक मुद्रा (एम$_3$) में एक वर्ष पहले की 14.1 प्रतिशत की वृद्धि के और ऊपर 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2002-03 के दौरान 14.0 प्रतिशत अनुमानित स्तर के अनुरूप थी। इसके घटकों में, 2002-03 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमाराशियां कुछ उच्चतर थीं (इसमें विलयन का प्रभाव भी शामिल है)। औद्योगिक उत्पादन में तेजी को दर्शाते हुए वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में निरन्तर वृद्धि बनी रही। 2002-03 के दौरान (विलयन के लिए समायोजन सहित) खाद्येतर ऋण तथा सरकारी प्रतिभूतियों, इन दोनों में वृद्धि काफी उच्चतर रही। बैंकों से इतर संस्थाओं, जिनमें ग्लोबल तथा अमरीकन डिपोजिटरी रसीद और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड तथा वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम भी शामिल हैं; से भी भारी संसाधन प्रवाह रहा।

* चूँकि यह रिपोर्ट 2002-03 से संबंधित है, अंत: इस अध्याय का मुख्य ध्यान वर्ष 2002-03 पर केन्द्रित रहा है।

1.6 इस पृष्ठभूमि में, वर्ष 2002-03 के दौरान रिज़र्व बैंक तथा की मौद्रिक नीति का समग्र बल ऋण की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त चलनिधि का प्रावधान करने तथा अर्थव्यवस्था में निवेश की मांग का समर्थन करने पर रहा। साथ ही, ब्याज दरों को नरम बनाये रखने के प्रति वरीयता जारी रखने तथा मूल्यों के स्तर में होनेवाली घटबढ़ पर निगरानी रखने पर ध्यान केन्द्रित रहा। उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुरूप, नकदी प्रारक्षित अनुपात को 5.5 प्रतिशत से घटाकर जून 2002 में 5.0 प्रतिशत तथा नवम्बर 2002 में और घटाकर 4.75 प्रतिशत कर दिया गया। इससे बैंकों के उधार देने योग्य संसाधनों में लगभग 10,000 करोड़ रु. की वृद्धि हुई। बैंक दर और रिपो दर रिज़र्व बैंक की नीतिगत संकेत देने के लिए प्रमुख साधन के रूप में उभरे। अक्तूबर 2002 में, बैंक दर को घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया गया। रिपो दर को भी घटाकर जून 2002 में 5.75 प्रतिशत तथा मार्च 2003 तक दो चरणों में और घटाकर इसे 5 प्रतिशत तक ले आया गया।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक :

1.7 वर्ष 2002-03 भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की मजबूत आय का वर्ष रहा जिसने प्रमुख आय की सभी श्रेणियों में उल्लेखनीय सुधार दर्शाये। आस्तियों पर प्रतिलाभ (अर्थात कुल आस्तियों के प्रति निवल लाभ का अनुपात) में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 2002-03 में 1.0 प्रतिशत का उल्लेखनीय सुधार देखा गया - यह गत 6 वर्षों में सबसे अधिक रहा। निम्नतम ब्याज दरें खुदरा और आवास घटक को प्रेरित करती रही हैं जिससे बैंकों की उधार से आय और सेवा शुल्क से होनेवाली आय - दोनों में वृद्धि हुई।

1.8 बाजार में अत्यधिक चलनिधि से उत्पन्न ह्रासमान आय तथा नरम ब्याज दरों की स्थितियों के परिणामस्वरूप सरकारी प्रतिभूति बाजार में आये उछाल को देखते हुए बैंकिंग उद्योग ने वर्ष के अधिकांश भागमें सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के क्षेत्र में उल्लेखनीय गतिविधियां दर्शायी। तथापि, वर्ष 2002-03 की अंतिम तिमाही के दौरान कुछ मंदी की प्रवृत्ति दिखाई दी, इन गतिविधियों के होते हुए भी बैंकिंग उद्योग ने समग्र रूप में वर्ष 2002-03 के दौरान अपने कार्य-निष्पादन में तीव्र सुधार दर्शाया जो कि मुख्य रूप से ब्याज व्यय में आयी कमी के कारण रहा (सारणी 1.1)।

1.9 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार सभी बैंक समूहों के कार्य-निष्पादन में आये व्यापक विचलन को ढक देता है। उदाहरण के लिए, आय में वृद्धि निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के लिए निम्नतम थी। जिसका कारण था - ब्याज आय में मामूली-सी वृद्धि का होना। दूसरी ओर, विदेशी बैंकों ने आय और व्यय दोनों में गिरावट का अनुभव किया जिसमें व्यय में आयी गिरावट ने आय में आयी गिरावट को पीछे छोड़ दिया, जोकि मुख्य रूप से ब्याज व्यय में हुई कमी के कारण रहा। सहज चल निधि की स्थिति से फायदा उठाते हुए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने अपने ब्याज व्यय को तर्कसम्मत स्तरों तक सीमित बनाये रखा। गिरती हुई ब्याज की दरों ने भी बैंकों को मूल्यवर्धित प्रतिभूतियों की बिक्री पर हुए लाभों को वसूल करने में सहायता की। अधिकांश बैंक समूहों के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं के लिए वृद्धि हुई जो यह दर्शाती है कि ऋण संविभाग में सुधार लाने के लिए इन बैंकों ने अपनी ओर से काफी मूल्य वृद्धि की है। इसके अपवाद विदेशी बैंक रहे हैं, जिनके लिए, वास्तव में, प्रावधानों में गिरावट की गयी जो उनके आस्ति-संविभागों में सुधार को दर्शाते हैं।

1.10 बैंकिंग क्षेत्र के पूंजी की स्तरों में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय सुधार हुआ। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का समग्र पूंजी-पर्याप्तता अनुपात मार्च 1997 के अंत के 10.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2003 के अंत में 12.6 प्रतिशत हो गया, जिसका कारण था - उन्होंने अपने लाभों को पुनः अपनी प्रारक्षित भंडार में निवेश किया। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक का पूंजी अनुपात प्राप्त कर लिया। समग्र स्तर पर (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) 93 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से केवल दो ही बैंक 9.0 प्रतिशत की निर्धारित पूंजी-पर्याप्तता अनुपात को पूरा नहीं कर सके।

1.11 बैंकों के ऋण जोखिम प्रबंध में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया। बैंकिंग क्षेत्र के समग्र गैर-निष्पादक आस्तियों में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमी हुई और वे मार्च 2003 के अंत में सकल अग्रिमों के 8.8 प्रतिशत रह गये। यह स्थिति मुख्यतया बेहतर जोखिम प्रबंध के संव्यवहार तथा बेहतर ऋण वसूली के प्रयास - इन दोनों कारणों से बनी। हाल ही में पारित वित्तीय आस्तियां का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम ने बैंकों को जून 2003 के अंत तक 500 करोड़ रुपये की वसूली करने में समर्थ बना दिया। इस अधिनियम का इस संबंध में महत्त्वपूर्ण प्रभाव देखा गया। आस्ति गुणवत्ता में आये सुधार के बावजूद, बैंक अपने प्रावधानीकरण के स्तरों में वृद्धि लाने के लिए सक्रिय प्रयास करते रहे हैं । यह तथ्य से झलकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सकल गैर-निष्पादक ऋणों के प्रति संचित प्रावधानीकरण की राशि 2001-02 के 42.5 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 47.2 प्रतिशत हो गयी। इस बढ़ी हुई प्रावधानीकरण की राशि के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निवल अग्रिमों के प्रति निवल गैर-निष्पादक ऋणों में तीव्र गिरावट आयी और वे 2001-02 के 5.8 प्रतिशत से गिरकर 2002-03 में 4.5 प्रतिशत रह गये।

सारणी I.1 : चुनिन्दा वित्तीय क्षेत्र के संकेतक : 2001-02 *vis-à-vis* 2002-03

	वित्तीय संस्था		संकेतक	2001-02	2002-03
	1		2	3	4
I	**अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक**	क)	*प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि (प्रतिशत)*		
			कुल जमाराशियाँ	14.6	13.4 *
			खाद्येतर ऋण	13.6	18.6 *
			सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	20.9	27.3
		b)	*वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)*		
			परिचालनगत लाभ	1.9	2.4
			निवल लाभ	0.8	1.0
			स्प्रेड	2.6	2.8
		ग)	*गैर-निष्पादक आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)*		
			सकल एनपीए	10.4	8.8
			निवल एनपीए	5.5	4.4
II	**शहरी सहकारी बैंक**	क)	*प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि (प्रतिशत)*		
			जमाराशियाँ	15.1	9.1
			ऋण	14.1	4.5
		ख)	*वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)@*		
			परिचालनगत लाभ	1.5	1.3
			निवल लाभ	-0.9	-1.1
			स्प्रेड	2.2	2.1
		ग)	*निष्पादन रहित आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)*		
			सकल एनपीए	21.9	21.0
III	**अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ**	क)	*प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि (प्रतिशत)*[1]		
			मंजूरी	-39.9	-31.3
			संवितरण	-18.5	-30.5
		ख)	*वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)*[2]		
			परिचालनगत लाभ	1.6	1.4
			निवल लाभ	0.7	0.9
			स्प्रेड	0.6	0.7
		ग)	*निष्पादन रहित आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)*[2]		
			निवल एनपीए	8.8	10.6
IV	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ**	क)	*प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि (प्रतिशत)*		
			सार्वजनिक जमाराशियाँ	4.1	—
		ख)	*वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)*		
			निवल लाभ	-0.5	—
		ग)	*निष्पादन रहित आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)*[3]		
			निवल एनपीए	3.9	4.3 #

* विलयन के लिए समायोजित @ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित

\# आँकड़े सितम्बर 2002 से सम्बन्धित हैं।

1. इसमें आइडीबीआइ, आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, आइडीएफसी, सिडबी, आइबीसीएफ, आइसीआइसीआइ वेंचर, टीएफसीआइ, एलआइसी, यूटीआइ तथा जीआइसी शामिल हैं।
2. उसमें निम्न लिखित नौ वित्तीय संस्थाएँ शामिल हैं - आइडीबीआइ, आइएफ़सी, आइआइ बी आइ, आइडीएफ़सी, एक्ज़िम बैंक, टीएफ़सीआइ, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी।
3. विभिन्न व्याप्तियों सहित सूचना देनेवाली कम्पनियां।

1.12 प्रतिस्पर्धात्मक दबावों की विद्यमानता का अनुभव भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अधिकाधिक किया जा रहा है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए ब्याज मार्जिन ने जिसे ब्याज व्यय के ऊपर ब्याज आय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जाता है, और जिसे कुल आस्तियों द्वारा सामान्य कर दिया गया था, ने गिरने की प्रवृत्ति दर्शायी और यह 1995-96 के 3.1 प्रतिशत से गिरकर 2002-03 में 2.8 प्रतिशत रह गया। यह नरम ब्याज दरों की परिदृश्य से प्रभावित हुआ। इसके अलावा व्यय में कटौती और मानव संसाधनों के युक्तिसंगत करने के कारण हुआ, जैसा कि उनके परिचालन व्ययों में कटौती के रूप में देखा जा सकता है, साथ ही इसमें प्रौद्योगिकी के प्रभाव से होनेवाले लाभ भी उठाये गये।

सहकारी बैंक :

1.13 सहकारी बैंकों ने1998 के दशक के उत्तरार्ध में सुदृढ़ विस्तार के बाद समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संतुलित वृद्धि दर्शायी। सहकारी बैंकों की लाभप्रदता पूर्णतया संतोषजनक नहीं रह पायी। यह मुख्य रूप से ब्याज आय और व्यय के अंतराल में कमी आने के कारण हुई- विशेषकर, चूंकि सहकारी बैंक, आम तौर पर, सरकारी प्रतिभूति बाजार में लेनदेन नहीं करते हैं और इस प्रकार वे अपने हित में अन्य गिरती हुई ब्याज दरों का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं रहे। साथ ही उनकी अग्रिमों के अनुपात में शहरी सहकारी बैंकों के मामले में आस्ति गुणवत्ता में भी कुछ सुधार हुआ और उनकी सकल गैर-निष्पादक आस्तियों में 2002-03 के दौरान मामूली-सी गिरावट दर्ज की गयी।

1.14 ग्रामीण सहकारी बैंकों का कार्य-निष्पादन भी दीर्घकालीन प्रवृत्ति के अनुरूप रहा। राज्य सहकारी बैंकों की लाभप्रदता वर्ष 2002-03 के दौरान मजबूत बनी रही। ग्रामीण सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियां उच्च बनी रहीं - उनकी टीयर-II पूंजी की आस्ति गुणवत्ता, उनकी टीयर-I पूंजी आस्ति गुणवत्ता की तुलना में खराब रही।

वित्तीय संस्थाएं :

1.15 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं[1] द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता में तेजी से गिरती हुई प्रवृत्ति, जो हाल की अवधि में देखी गयी, वर्ष 2002-03 में भी जारी रही, जब वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सहायता का समायोजन चुकौतियों के लिए सकल पूंजी बर्हिगम के लिए किया जाता है, तो वित्तीय संस्थाओं से कम्पनियों के लिए संसाधनों का प्रवाह नकरात्मक पाया जाता है। आइसीआइसीआइ का आइसीआइसीआइ बैंक के साथ विलयन तथा कुछ वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्रों के आकार में आम तौर पर पायी गयी कमी, वित्तीय सहायता में इस गिरावट को काफी सीमा तक स्पष्ट करती है। वित्तीय संस्थाओं का कम हुआ कार्य-निष्पादन भारतीय उद्योगों के लिए वित्तपोषण के स्वरूप में वित्तीय संस्थाओं के घटते हुए सामान्य योगदान के अनुरूप है। इसके अलवा, नरम पूंजी बाजार, नयी परियोजनाओं के लिए मांग की कमी और विद्यमान अप्रयुकत क्षमताओं का उपयोग करके औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि- इन सभी ने दीर्घावधि वित्तीय सहायता के लिए मांग में कमी लाने में योगदान किया होगा।

1.16 एक समूह के रूप में, चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्र ने पिछले वर्ष से आगे 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है, तथापि, देयताओं और आस्तियों का स्वरूप मोटे तौर पर वैसा ही रहा। देयताओं की दृष्टि से, कुल देयताओं में, बांड और डिबेंचरों का मुख्य अंश रहा, क्योंकि वे कॉल और पुट आप्शंस के साथ आर्थिक संरचना में अधिक नमनीयता उपलब्ध कराते हैं, साथ ही, उनके स्टॉक बाजार में सूचीबद्ध कराकर द्वितीयक बाजार में बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। (आइसीआइसीआइ को छोड़कर) वित्तीय संस्थाओं के कुल संसाधन और निधियों के विनियोजन में 2002-03 के दौरान 2.1 प्रतिशत की गिरावट आयी, जबकि पिछले वर्ष इनमें 19.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जोखिम भारित आस्तियों के प्रति न्यूनतम पूंजी अनुपात (सीआरएआर) को बनाये रखने के संबंध में चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं का कार्य-निष्पादन यह प्रकट करता है कि आइएफसीआइ और आइआइबीआइ को छोड़कर, सभी वित्तीय संस्थाओं ने 2002-03 के दौरान अपने सीआरएआर को 9 प्रतिशत के मानदण्ड से काफी ऊपर बनाये रखा। तथापि, 2002-03 के दौरान कुछ चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की निवल गैर-निष्पादक ऋणों में वृद्धि हुई।

1.17 पारस्परिक निधियों द्वारा संसाधन संग्रहणों में 2002-03 में तेजी से गिरावट आयी, इसका मुख्य कारण था - यूटीआइ से, जिसका वर्ष के दौरान पुनर्गठन किया गया, निधियों का भारी मात्रा में निवल बर्हिवाह। निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियों ने भी निधियों के संग्रहण में तेज गिरावट दर्ज की, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की निधियों ने (यूटीआइ को छोड़कर) मामूली-सी वृद्धि दर्ज की।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां

1.18 जमाराशियां स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया 2002-03 के दौरान पूरी कर ली गयी। तथापि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की संख्या में वर्ष के दौरान गिरावट आयी जो अनेक कारकों के मेल को दर्शाती है जैसे - विलयन, समापन, लाइसेंसों का निरस्तीकरण। जमाराशियां स्वीकार करनेवाली कम्पनियों की संख्या में इसलिए भी गिरावट आयी क्योंकि गैर-सार्वजनिक जमाराशियों स्वीकरण से संबंधित गतिविधियों का रूपान्तरण हो गया। साथ ही,गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के तुलनपत्र विवेकसम्मत मानदंडों के परिणामस्वरूप, हाल के वर्षों में मजबूत होते रहे हैं। पूंजी-पर्याप्तता की दृष्टि से, अधिकांश सूचना देनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने कम से कम 12 प्रतिशत की न्यूनतम निर्दिष्ट जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) दर्ज किया। सूचना देनेवाली लगभग 3/4 कम्पनियों ने 30 प्रतिशत से अधिक का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात दर्ज किया। इसके अलावा, गैर-निष्पादक आस्तियां भी, सकल और निवल दोनों दृष्टियों से, ऋण-जोखिम के प्रतिशत के रूप में घटती रही हैं ।

1.19 तथापि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के वित्तीय परिणाम कम संतोषजनक रहे। वास्तव में, इस क्षेत्र ने समग्र रूप से वर्ष 2001-02 के दौरान लगातार दूसरे वर्ष भी हानियां दर्ज कीं। निधि-आधारित और

[1] इसमें आइडीबीआइ, आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, सिड़बी, आइसीआइसीआइ (2001-02 तक), आइवीसीएफ, आइसीआइसीआइ बेंचर, टीएफसीआइ, एलआइसी, यूटीआइ और जीआइसी शामिल हैं।

शुल्क-आधारित दोनों प्रकार की आयों में गिरावट रही। व्यय में कमी भी मामूली-सी रही, क्योंकि परिचालनगत व्यय और कर-प्रावधान भारी बने रहे।गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए वर्ष 2002-03 के कार्य-निष्पादन संबंधी संकेतक भी मिलने अभी बाकी हैं। तथापि व्यापक चलनिधि पर तिमाही आंकड़े (एल$_3$)जिसमें बैंकिंग क्षेत्र, डाकघर बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की मौद्रिक और चल निधि देयताएं शामिल हैं, यह दर्शाती हैं कि सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की सार्वजनिक जमाराशियों के अंश ने 2002-03 के दौरान मामूली-सी वृद्धि दर्ज की।

1.20 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम में यह प्रावधान है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी वित्तीय आस्तियां प्रतिभूतिकरण कम्पनियों अथवा पुनर्निर्माण कम्पनियों को बेची जा सकती हैं। हाल ही में आइडीबीआइ, आइसीआइसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तथा कुछ अन्य बैंकों ने संयुक्त रूप से 20 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी तथा 10 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी के साथ एक सक्रिय आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड का गठन किया है। आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड को अपने परिचालन शुरू करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लाइसेन्स प्रदान कर दिया है।

2003-04 के दौरान गतिविधियां

1.21 भारतीय अर्थव्यवस्था 2003-04 के दौरान तीव्र वृद्धि दर्ज करने की स्थिति में है। पहली तिमाही (अप्रैल-जुलाई 2003) के दौरान सकल देशी उत्पाद में वृद्धि पिछले वर्ष की तदनुरूपी तिमाही की तुलना में बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो गयी। एक वर्ष के सुखा के बाद सामान्य मानसून रहने के कारण कृषि के उत्पादन में सुधार होने की सम्भावना है। इसके अलावा, औद्योगिक वृद्धि भी लगातार सुदृढ़ बनी हुई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि 2003-04 (अप्रैल-से अगस्त) के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 5.2 प्रतिशत से बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गयी। इस वृद्धि के पीछे विनिर्माण क्षेत्र में बेहतर सुधार का योगदान रहा। आधारभूत वस्तुएं, पूंजीगत माल और उपभोक्ता वस्तुओं में निरन्तर वृद्धि होने के संकेत हैं। इन सभी कारकों के फलस्वरूप 2003-04 के दौरान, सकल देशी उत्पाद में समग्र वृद्धि 6.5-7.0 प्रतिशत रहने की सम्भावना है, जो और भी बढ़ने की ओर उन्मुख है। पूंजी प्रवाहों में तेज वृद्धि वर्ष 2003-04 के दौरान (अक्तूबर तक) बनी रही, जो विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों में बहाली से और बढ़े। इसके परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार अक्तूबर 2003 के अंत तक बढ़कर 92.6 बिलियन अमरीकी डालर का हो गया। भारतीय रुपयों की विनिमय दर जो मार्च 2003 के अंत में एक डालर के प्रति रु.47.50, रुपये थी, बढ़कर अक्तूबर 2003 के अंत में एक डालर = 45.32 रुपया हो गयी। परन्तु इसी अवधि में इसमें यूरों की तुलना में 23 प्रतिशत, पौंड स्टर्लिंग की तुलना में 25 प्रतिशत की तथा जापानी येन की तुलना में 42 प्रतिशत की मूल्यह्रास हो गया। अप्रैल-सितंबर 2003 के दौरान निर्यात वृद्धि में मंदी रही, वहीं पिछली वर्ष की इसी अवधि की तुलना में आयातों में वृद्धि हुई।

1.22 चलनिधि की स्थितियां सहज बनी रहीं, जो सुदृढ़ पूंजी प्रवाहों से प्रेरित थी। व्यापक मुद्रा (एम$_3$) की वृद्धि इस वर्ष के दौरान (17 अक्तूबर 2003 तक) 7.4 प्रतिशत रही । जो 2002-03 की तदनुरूपी अवधि में विलयन के लिए समायोजन के बाद देखी गयी 8.1 प्रतिशत की वृद्धि से निम्न थी। यह वृद्धि अप्रैल 2003 की मौद्रिक और ऋण नीति में किए गए अनुमानों के भीतर रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की खाद्येतर ऋण की निकासी 17 अक्तूबर 2003 तक विलयन प्रवाहों को समाहित करके 5.7 प्रतिशत रही जो पिछले वर्ष की तुलनीय अवधि के 7.4 प्रतिशत से कुछ कम थी। तथापि, ऋण बाज़ार में कुछ नयी प्रवृत्तियां जैसे खुदरा ऋण में वृद्धि, विशेषकर, आवास क्षेत्र में, उल्लेखनीय रही। वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति दर-बिन्दु-दर आधार पर 2003-04 के पहले दो महीनों के दौरान 6.3-6.9 प्रतिशत रही। इसके बाद यह 18 अक्तूबर तक गिरकर 5.0 प्रतिशत पर आ गयी।

1.23 सहज चलनिधि की स्थितियों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा रिपो दरों में की गयी कटौती को दर्शाते हुए,ब्याज दरें वित्तीय बाजारों में और नरम बनी रहीं। दूसरा अच्छा पहलू वर्ष के दौरान यह रहा कि पूंजी बाजार में सुधार हुआ जिसमें बीएसई संवेदी सूचकांक वर्ष 2003-04 के दौरान (अक्तूबर के अंत तक) 61 प्रतिशत बिन्दुओं तक बढ़ गया।

1.24 जून 2003 को समाप्त तिमाही के दौरान वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली का कार्य-निष्पादन, जैसा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पर्यवेक्षी विवरणियों से प्रकट होता है, पिछले वर्ष की तदनुरूपी तिमाही की तुलना में इस वर्ष अपने कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। जून 2003 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों के प्रति निवल लाभ 0.32 प्रतिशत रहा, जबकि, जून 2002 के अंत में यह 0.24 प्रतिशत था। निवल लाभ में जो सुधार हुआ, वह आम तौर पर व्ययों को सीमित रखने के कारण रहा, विशेषकर ब्याज व्ययों को कम करने के कारण था। ये उपलब्धियां सभी बैंक समूहों की प्रावधानीकरण और आकस्मिक देयताओं में तेज वृद्धि के रहते हुए प्राप्त की गयी। कुल मिलाकर परिचालनगत व्यय जून 2002 के अंत के स्तर पर ही बना रहा। इसका अपवाद निजी क्षेत्र के बैंक रहे जिनके लिए इन व्ययों में मामूली-सी वृद्धि हुई। इसका कारण था- औद्योगिक वृद्धि में सुधार को दर्शाते हुए वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता अप्रैल-सितम्बर 2003 के दौरान बढ़ी।